

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोन:- 2418945 फैक्स:- 0294-2410146

वर्ष: 33

संख्या: 53

प्रभात

उदयपुर, बुधवार 24 दिसम्बर, 2025

आर.जे. 7202

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

पूरे पुराने बंगाल प्रांत में हिंसा का इतना भयानक दौर पहले नहीं आया

दुष्कर्म मामले में आईपीएल क्रिकेटर को अग्रिम जमानत नहीं मिली

जयपुर, 23 दिसंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में आईपीएल क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी अलका बंसल ने कहा कि आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक गैंग काम कर रही है। उसके खिलाफ पहले गाजियाबाद में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर

■ **पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने क्रिकेटर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।**

कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। इसके सात दिन बाद ही सांगानेर सदर थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया और इसे गंभीर रूप देने के लिए लड़की ने घटना दो साल पहले की बताई जब वह नाबालिग थी। अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया कि यश दयाल पेशेवर क्रिकेटर है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। इसके अलावा वह प्रकरण की जांच में सहयोग करने को तैयार है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देश भर में फैल रहा है अरावली आंदोलन

सचिन पायलट ने राजस्थान के 19 जिलों में अरावली बचाओ आंदोलन की घोषणा की

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 23 दिसंबर। अरावली के मसले पर विरोध प्रदर्शन तीव्र होता जा रहा है और राजनीतिक दल भी इस मुद्दे में कूद पड़े हैं, और पर्यावरणविद् और पर्यावरण से जुड़े एक्टिविस्ट भी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में सड़कों पर उतर आए हैं।

राजस्थान में कांग्रेस ने 19 जिलों में “अरावली बचाओ आंदोलन” का ऐलान किया है, और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए चेतावनी दी कि खनन गतिविधियों में वृद्धि से न केवल राजस्थान और हरियाणा, बल्कि दिल्ली एनसीआर में भी इकोलॉजिकल संकट उत्पन्न हो सकता है।

शिवसेना (उद्धव बाल ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने भी सोशल मीडिया पर कई पोस्टर करते हुए एनडीए सरकार को ”प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने की आदत” की कड़ी आलोचना की है, और अरावली पर्वतों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये पर्वत देश की जलवायु और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से हुई है, जिसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित

■ देश भर के पर्यावरणविद्, एक्टिविस्ट व वकील अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे।

■ शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में अरावली का पर्यावरण के लिए महत्व बताया और एनडीए सरकार पर प्राकृतिक संपदाएं नष्ट करने का आरोप लगाया।

■ हालांकि, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मामला शांत करने की कोशिश की और कहा कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर का 0.19 प्रतिशत हिस्सा ही खनन के लिए लीज़ पर दिया जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर अरावली में अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

■ विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर सरकार की नई परिभाषा को स्वीकार करने से हुई, जिसके तहत जमीन से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। विपक्ष और विशेषज्ञों का आरोप है कि अरावली पर्वत शृंखला में 12,000 पहाड़ियां हैं और इनमें से मात्र 8 प्रतिशत ही 100 मीटर से ऊंची हैं।

अरावली की नई परिभाषा को स्वीकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, केवल वे पहाड़ियां जो स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर ऊंची होंगी, उन्हें ही अरावली पहाड़ियां माना जाएगा। ऐसी दो या दो से अधिक

पहाड़ियां जो 500 मीटर के भीतर स्थित होंगी, उन्हें बीच की भूमि सहित अरावली रेंज में माना जाएगा। एक्टिविस्ट, वकीलों और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अंकिता भंडारी मर्डर, एक वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता मर्डर केस में आरोप -प्रत्यारोप का नया दौर शुरु कर दिया है

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या के मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, और सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व को नए सिरे से जांच के घेरे में ला खड़ा किया है। इस वीडियो ने ताजा आरोपों और सीबीआई जांच की मांगों को जन्म दिया है, जिसमें एक कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की जा रही है।

यह वीडियो, जो पिछले कुछ दिनों से व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, में कथित रूप से हरिद्वार के पूर्व भाजपा विधायक सुरेश चौहान अपनी पत्नी उर्मिलाना सनावर के साथ तीखी बहस करते दिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने दावा

■ **उक्त वीडियो में हरिद्वार के पूर्व विधायक अपनी पत्नी, (पूर्व अभिनेत्री) उर्मिला सनावर के साथ तीखी बहस में यह कहते दिख रहे हैं कि ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में हुई 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या में उत्तराखंड के भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने अंकिता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था।**

■ **उर्मिला सनावर ने भी सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उसके पास इन आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत भी हैं।**

■ **कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले में कोर्ट की निगरानी में नए सिरे से सीबीआई जांच करवाई जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अपराधियों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करवाई।**

किया है कि उत्तराखंड के लिए भाजपा के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम अंकिता भंडारी की हत्या

के पीछे प्रमुख आरोपी थे। चौहान यह आरोप लगाते हुए सुने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति ने 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिये

नयी दिल्ली, 24 दिसम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 24 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार– 2025 प्रदान किए।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दूसरे संस्करण में उल्लेखनीय कार्यों के लिए

■ **प्रो. जयंत विष्णु नालींकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।**

वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। खगोल भौतिकी विशेषज्ञ, दिवंगत प्रो. जयंत विष्णु नालींकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डा. ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह और सात अन्य को विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया।

बांग्लादेश उच्चायोग पर भारतीयों का गुस्सा फूटा

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के मेमनसिंह में इस्लामी भीड़ द्वारा एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद, नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। यह प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों और उनके धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के खिलाफ नारे लगाए गए।

प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई और उन्होंने बांग्लादेशी अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करते हुए बैरिकेड तोड़ दिए। कुछ प्रदर्शनकारी न्याय और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

तनाव तब बढ़ गया जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड को धक्का देना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी “भारत माता की जय”, “यूनस सरकार होश में आओ” और “हिंदू हत्या बंद करो” के नारे लगा रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने कम से कम दो स्तर के बैरिकेड तोड़ दिए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, अगर

प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़े और बैरिकेड्स फांदकर अंदर घुसे, यूनस के पुतले भी जलाए

■ **प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में गत दिनों एक हिंदू, दीपूचन्द्र दास की नृशंस हत्या पर नारज़गी जताई और कहा कि हिंदुओं की हत्या के लिए बांग्लादेश सरकार ही जिम्मेवार है। यह प्रदर्शन विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने आहूत किया था।**

■ **बांग्लादेश सरकार ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष विरोध प्रदर्शन की इस घटना पर नाराज़गी जताई और आरोप लगाया कि नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा कम की गई है। भारत ने इस आरोप से साफ इनकार किया।**

आज हमने अवाज नहीं उठाई, तो मैं भी दीपू बर्गुंगा और आप भी दीपू बर्गेगे। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। यह (भारत) राम और कृष्ण की भूमि है। हम किसी को नहीं मारते, लेकिन वहां हमारी बहन-बेटियां के साथ बलात्कार किया जा रहा है।” कई प्रदर्शनकारियों को बैनर और तस्वियां पकड़े हुए देखा गया, जिन पर दीपू दास के लिए न्याय की मांग लिखी

थी। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनस के पुतले भी जलाए।

पुलिस हालात को संभालने और इलाके को खाली कराने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है। पुलिस ने दोबारा बैरिकेडिंग भी स्थापित कर दी है।

प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क थीं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने

के लिए इमारत के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूरे इलाके में तीन स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया था।

ज्ञातव्य है कि पच्चीस वर्षीय गारमेट फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्र दास को 18 दिसंबर को मेमनसिंह के बालुका इलाके में कथित इशनिंदा के आरोप में भीड़ ने घाट-घाटकर मार डाला और उसके शव को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद व्यापक आक्रोश और निंदा देखने को मिली।

हत्या में कथित भूमिका के लिए अब तक कम से कम 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

दिन में पहले बांग्लादेश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन पर हुए हमलों को लेकर चिंता जताई और नई दिल्ली व सिलीगुड़ी की घटनाओं के विरोध में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घाटे में चल रही पाकिस्तान एयरलाइन नीलाम हुई

इस्लामाबाद, 23 दिसंबर। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन (पीआईए) लंबे समय से घाटे में चलने की वजह से बिक गई। आरिफ हबीब ग्रुप ने सबसे ऊंची, 135 अरब पाकिस्तानी रुपये की बोली लगाकर पीआईए को खरीद लिया है। लकी सीमेंट ने 101.5 अरब रुपये और एयरब्लू ने 26.5 अरब रुपये की बोली लगाई। पीआईए ने 7.5 फीसदी शेयरों की नीलामी शुरू की थी।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन को नीलामी से मिलने वाले कुल पैसे का 92.5 फीसदी एयरलाइन के सुधार पर खर्च होगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट्स की कमी, खराब मैनेजमेंट और भारी कर्ज जैसे कारणों की वजह से पीआईए की हालत खराब हुई।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने प्रधानमंत्री के सहायक और उनकी टीम को नीलामी प्रक्रिया के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, आज हम जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने में बहुत समय और मेहनत लगती है।

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK

विचार बिन्दु

पराधीनता समाज के समस्त मौलिक निमयों के विरुद्ध है। —मान्तेस्कुय

मीडिया में बज़ बनाकर हक़ीकतें बदलने की कोशिश

लोकतंत्र की आत्मा लोक कल्याणकारी शासन में निहित होती है। एक सुशासित राज्य में सरकार करदाताओं के धन से ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाती हैं जिनका लक्ष्य आम नागरिक के जीवन में ठोस, स्थायी और न्यायपूर्ण परिवर्तन तथा समानता लाना होता है। इस काम के लिए भारतीय संविधान में विधायिका की व्यवस्था है, जिसमें निर्वाचित जन प्रतिनिधि विधियां, नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं जिन्हें कार्यपालिका क्रियान्वित करती है। किंतु इक्कीसवीं सदी के ढाई दशक के बीत रहे काल में आज एक विचित्र और चिंताजनक हालत सामने है। जन-कल्याण के नाम पर घोषित अनेक कार्यक्रम ज़मीन पर दिखाई नहीं देते, जबकि सरकारें मीडिया में बज़ बनाए रखने के लिए भव्य इवेंट, उद्घाटन, शिलान्यास, उत्सव और प्रचार अभियानों पर अपना अधिकतम ध्यान और संसाधन झोंक रही हैं। यह प्रवृत्ति न केवल कार्यपालिका को शिथिल कर रही है, बल्कि व्यवस्था में पहले से मौजूद भ्रष्टाचार को और गहरा कर रही है। राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के दो वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में जश्न मनाए जा रहे हैं। राजधानी में सत्ता के शीर्ष पर शासन के नीचे तक के तंत्र को स्पष्ट हिदायतें भेजी गई हैं कि इस जश्न के लिए रोज़ कौन-कौन से इवेंट किए जाने हैं। इसके साथ ही प्रलिटिन चौकसी और निगरानी की जा रही है कि जो बातयागना सड़क हो रहा है या नहीं। यहां तक कि कार्यपालिका के प्रमुख मुख्य सचिव खुद जिला अधिकारियों से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। अधिकारियों व अन्य कर्मियों को हिदायतें दी गई हैं कि जो भी इवेंट हो उसके चित्र और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाए। प्रचार विभाग की सोशल मीडिया पोस्टों को आगे अपने स्टार पर बढाया जाए। इस की सतत निगरानी होती है और चूक पर फटकारें पड़ती हैं। चाहना यह है कि धरती पर कोई काम हुआ हो या न हो उसके प्रचार का तुफान खड़ा कर दिया जाए। जो इवेंट किए जा रहे हैं उनके परिणामों पर नहीं बल्कि उनके भरपूर प्रचार किए जाने पर एकमात्र जोर है। मान लिया गया है कि धुआं-धारा प्रचार मतदाताओं तक पहुंच कर सत्तारूढ़ दल की मदद करेगा। मुख्य सचिव ने अपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा कि बज़ क्रियेट कीजिए। ऐसी बातें प्रचार व्यवसाय को भाती हैं। बाज़ार की ताकतों ने राजनेताओं को यह घुट्टी पिला दी है कि प्रचार की आंधी से चुनाव जीते जा सकते हैं। यह कोई याद नहीं दिलाता कि पिछली अशोक गहलोत की सरकार ने फिर कुर्सी पाने की ताबड़तोड़ में प्रचार के भ्रष्टाचार का जो अंबार खड़ा किया उस पर मतदाता की समझ भारी पड़ी थी। बाज़ार के सौदागरों ने नई सरकार को भी प्रचार के चमक-दमक की बही राह दिखा दी है जिस पर होर्डिंस बही है, केवल राजनेताओं के चित्र बदले हुए हैं। जनकल्याण का अर्थ होता हैनिरंतरता, निगरानी, जवाबदेही और परिणाम। इसके विपरीत, इवेंट-आधारित शासन का मूल तत्व होता है दिखावा, सुर्खियां और छवि-प्रबंधन। सड़क, स्कूल, अस्पताल, पानी, स्वच्छता, पोषण, रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार का असर महीनों-सालों में दिखता है; जबकि एक भव्य कार्यक्रम का प्रभाव कैमरों की चमक तक सीमित रहता है। यही कारण है कि प्रदर्शनकारी शासन त्वरित संतोष देता है। उसके नेताओं को तालियां, प्रशंसा को फोटो-ऑप्स और सत्ता को कथानक (नैरेटिव) मिल जाता है। परिणामस्वरूप, लोक-कल्याण का वास्तविक काम पीछे छूट जाता है।

भ्रष्टाचार का पोषण प्रशासनिक शिथिलता से होता है। जब शासन का केंद्र बिंदु परिणाम नहीं, बल्कि प्रस्तुति बन जाए, तो भ्रष्टाचार के लिए उर्वर भूमि तैयार होती है। इवेंट-आधारित मॉडल में टेके, टेंट, लाइटिंग, विज्ञापन, ब्रांडिंग, यात्रा और आतिथ्य, इन समूह में त्वरित भुगतान, कम पारदर्शिता और आपात निर्णयों की खूब गुंजाइश रहती है। यह कम समय-अधिक खर्च का वह रास्ता है जहां कमोशान संस्कृति सहज ही फलती-फूलती है। इसके विपरीत, किसी स्कूल की गुणवत्ता सुधार या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कार्यक्षमता बढ़ाने में निरंतर निरीक्षण, ऑडिट और सामुदायिक सहभागिता चाहिए जो इवेंट की तुलना में कम आकर्षक होती है। कार्यपालिका की शिथिलता इसी बिंदु से जन्म लेती है। अधिकारियों का मूल्यंकन परिणामों से नहीं, बल्कि कार्यक्रमों की सफलता या कवरेज से होने लगता है। ऐसे में फोल्ड वर्क गौण हो जाता है। फाइलें चलती हैं,

प्रस्तुतियां बनती हैं, पर निगरानी कमजोर पड़ जाती है। जवाबदेही का तंत्र ढीला हो जाता है

और भ्रष्टाचार सिस्टम की रा-रा में घुस जाता है। मीडिया, प्रचार और नैरेटिव का जालएक खतरनाक खेल है जिसे बाज़ार की लफंगी ताकतों ने जबरदस्त तरीके से साध रखा है। भले ही मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बता कर इतराया जाए, पर जब शासन का उद्देश्य केवल मीडिया में बने रहना बन जाए, तो सत्ता-मीडिया संबंध विकृत हो जाता है। विज्ञापन और प्रायोजित सामग्री के सहारे सकारात्मक कवरेज सुनिश्चित की जाती है, जबकि ज़मीनी सच्चाइयों-अधूरी योजनाओं, गुणवत्ताहीन निर्माण, सेवाओं की कमीके हालात को हाशिये

पर धकेल दिया जाता है। इस नैरेटिव-निर्माण में आंकड़ों की बाज़ीगरी, चयनित उपलब्धियां और आलोचनाओं का दमन शामिल हो जाता है। नतीजा यह होता है कि किसी दैनिक अखबार में किसी दिन सत्ता के नेतृत्व की उपलब्धियों के 13 पूरे पेजों के विज्ञापनों से नागरिकों को काम हुआ का भ्रम मिलता है, जबकि वास्तविकता अलग होती है। इवेंट-शासन संस्थाओं को कमजोर करते हैं। दुर्भाग्य से संस्थागत क्षरण और लोकतांत्रिक नुकसान अब किसी को नज़र नहीं आते।नीति निर्माण में विशेषज्ञता और डेटा का स्थान नारे ले लेते हैं। संसद-विधानसभाओं में बहस की जगह हंगामों के बीच घोषणाएं हावी हो जाती हैं। स्थानीय निकाय, जो जनकल्याण की रीढ़ होते हैं, उपेक्षित रहते हैं; क्योंकि वहां स्थानीय राजनीति के पच्चेडे होते हैं और उनकी उपलब्धियों की ज़मीनी हक़ीकत नागरिक रोज महसूस करते हैं जो किसी मंच-सज्जा से झुलझाई नहीं जा सकती। लोकतंत्र में नागरिक लाभाभी नहीं, हितधारक होते हैं। लेकिन जब शासन प्रदर्शन में बदल जाए, तो नागरिक दर्शक बन जाते हैं। वे आमंत्रित तालियां बजाने वाले हो जाते हैं। वे सवाल न पूछने वाले नागरिक बन दिए जाते हैं। यह व्यवस्था किसी को नहीं चुनौती, क्योंकि सभी के लिए यह सुभीती वाली होती है। संसाधनों की बर्बादी और लागत पर बुद्धिजीवियों का भी ध्यान नहीं जाता है। वे भी अपने-अपने इवेंट में व्यस्त रहते हैं। इवेंट और प्रचार पर किया जाने वाला धन यदि स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण, अस्पतालों में उपकरण, जल-प्रबंधन या रोजगार-सृजन के कार्यों पर लगे, तो स्थायी लाभ मिल सकता है। कोई यह कहने वाला नहीं मिलता है कि शासन की प्राथमिकताएं बदल जाने का दीर्घकालिक नुकसान अंततः समाज को ही होता है। गरीबी के चक्र, स्वास्थ्य संकट, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट को नज़रन्दाज़ करते हुए भविष्य की कीमत पर सत्ता अपने वर्तमान को चमकाने का प्रयास कर रही है। इस व्यवस्था में समाज में आर्थिक असमानता और नागरिकों में बेचैनी बढ़ती है, अपराधों का बोलबाला होता है। बड़ा नुकसान जवाबदेही के तंत्रों के क्षय का होता है। इवेंट-शासन में जवाबदेही धुंधली हो जाती है। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते, समय-सीमा ढीली रहती है और मापन के पैमाने बदल दिए जाते हैं। कितने कार्यक्रम हुए की गणना वीडियो कॉन्फ्रेंसों के जरिए होती है। सार्वजनिक सेवाओं में कितना सुधार हुआ की कोई गणना नहीं होती। कोई पूछता भी नहीं। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्टें अनसुनी रह जाती हैं। शिकायत-निवारण तंत्र निष्प्रभावी हो जाते हैं। प्रचार से असफलताओं को ढक दिये जाने वाले निज़ाम में सुधार की प्रेरणा की कल्पना कैसे की जा सकती है! ऐसे में सामाजिक और लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर से विश्वास उठने लगता है। सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास ही शासन की पूंजी होती है। बार-बार के वादे, भव्य घोषणाएं और ज़मीनी नاکामी इस विश्वास को क्षत-विक्षत कर देती हैं। लोग व्यवस्था से विमुख होते हैं; निराशा और आक्रोश बढ़ता है। कानून को धत्ता बताई जाने लगती है। अपराध सामान्य चलन बन जाता है। यह सब मिल कर अंततः सामाजिक ताने-बाने और लोकतांत्रिक स्थिरता-दोनों के लिए खतरनाक हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि समाधान की कोई दिशा न हो। परिणाम-आधारित शासन के लिए ज़मीन तैयार करनी होगी। सड़के लिए राजनीतिक रुझानबिंदु और नागरिक दबाव साथ ही तभी बात बन सकती है। शासन में परिणाम-आधारित मूल्यंकन से ऐसा हो सकता है। अधिकारियों और विभागों का आकलन स्पष्ट, मापने योग्य परिणामों से हो, जैसे सीखने के स्तर, स्वास्थ्य संकेतक, सेवा-डिलीवरी समय आदि। सरकारों खर्चों में पारदर्शिता हो। इवेंट और प्रचार व्यय पर सीमा तय हो और सभी खर्च सार्वजनिक डैशबोर्ड पर साफ-साफ दिखें। समयबद्ध ऑडिट, सामाजिक ऑडिट और स्थानीय समुदाय की भागीदारी अनिवार्य हो। यहां मीडिया की जिम्मेदारी आती है। उसे विज्ञापन-समाचार की स्पष्ट रेखा खींचनी होगी और ज़मीनी रिपोर्टिंग की अहमियत समझनी होगी। स्थानीय निकायों के काम काज की निगरानी में नागरिकों की भागीदारी बनानी होगी। वर्तमान चुनावी व्यवस्था के बाहर भी कुछ करना होगा। कानूनी जवाबदेहीभी ज़रूरी है भ्रष्टाचार और लापरवाही पर त्वरित दंड मिले और व्हिस्लब्लोअर को सुरक्षा मिले। मगर असली बात होगी नागरिक जागरूकता। नागरिक सवाल पूछें और खड़े होकर हक सके कार्यक्रम नहीं, परिणाम दिखाइए। इवेंट-लोकतान्त्रिक शासन का विकल्प नहीं हो सकता। सत्ता में बैठे राजनेताओं को याद रखना होगा कि इतिहास मंच-सज्जा नहीं, परिणाम लिखता है। शासन को फिर से सेवा, सत्य और जवाबदेही के अपने मूल कर्तव्य की ओर लौटने से ही लोकतंत्र फल-फूल सकता है। यही लोकतंत्र की रक्षा और राष्ट्र के भविष्य का एकमात्र मार्ग है।

—अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राशिफल

बुधवार 24 दिसम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

आज रविवोग प्रातः 8:18 से आरम्भ होगा। भद्रा आज दिन 1:12 तक रहेगी। पंचक सायं 7:46 से आरम्भ होगा।**श्रेष्ठ चौघड़िया:** लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:52 तक, शुभ 11:09 से 12:26 तक, चर 3:01 से 4:18 तक, लाभ 4:18 से सूर्यास्त तक।**राहुकाल:** 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:17, सूर्यास्त 5:35 तक



मेष

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करो। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।



तुला

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में वृद्धि होगी।



वृश्चिक

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मिथुन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज नवीन कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।



धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरिपेशा व्यक्तियों की भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। संभावित धन प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।



मकर

व्यावसायिक कार्य से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरिपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।



सिंह

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।



कुंभ

आज समय अनर्गल कार्यों में व्यतीत होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।



मीन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

अरावली पर्वत श्रृंखला: अस्तित्व का संकट और भविष्य



अशोक कुमार

अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल भारत की, बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी है। आज, 2025 के परिप्रेक्ष्य में, अरावली केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं रह गई है, बल्कि यह उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के लिए अस्तित्व की जीवन रेखा बन चुकी है। इसे “दिल्ली-एनसीआर के फेफड़े” कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में यह फेफड़े शहरीकरण, अवैध खनन और प्रशासनिक अनदेखी के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

अरावली थार मरुस्थल की उड़ती हुई रेत को गंगा के उज्जाऊ मैदानों और दिल्ली-एनसीआर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करता है। यदि यह पहाड़ियां गायब हो गईं, तो उपजाऊ कृषि भूमि

मरुस्थल में बदल जाएगी। अरावली की दरारयुक्त चट्टानी संरचना वर्षा जल को जमीन के नीचे भेजने के लिए एक स्पंज की तरह काम करती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के गिरते भूजल स्तर के बीच, अरावली ही एकमात्र माध्यम है जो एक्विफर को रिचार्ज करता है। एनसीआर क्षेत्र दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शुमार है। अरावली के घने जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने का प्राथमिक स्रोत है। यह क्षेत्र तेंदुओं, नीलगाय, सियार, धारीदार लकड़बघा और पक्षियों की सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। यह राजस्थान के सरिस्का से लेकर हरियाणा के असोला भट्टी तक वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित गलियारा प्रदान करता है।

राजस्थान में अरावली का विस्तार सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ यह माफियाओं के निशाने पर है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एकरिपोर्ट ने देश को झकझोर दिया था, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियाँ पूरी तरह गायब हो चुकी हैं।

2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, अवैध खनन की यह समस्या और गंभीर हुई है। पहाड़ियों के समतल होने के कारण धूल भरी आंधियों की लो़त्रता अब साल के अधिकांश समय दिल्ली को प्रभावित करती है। हरियाणा के मुहनाम और फरीदाबाद जिलों में अरावली को बचाने के लिए

वर्तमान में तीन स्तरों पर लड़ाई लड़ी जा रही है:सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि “अरावली में कोई भी गैर-वानिकी गतिविधि नहीं होगी।” कोर्ट ने हरियाणा सरकार को खोरी गाँव जैसे अतिक्रमण हटाने और वन भूमि को पुनर्जीवित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार ने अरावली के किनारे 1,400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी अरावली ग्रीन वॉल बनाने की योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पोरबंदर से पानीपत तक वृक्षारोपण के माध्यम से मरुस्थलीकरण को रोकना है।

अरावली बचाओ सिटिजन मूवमेंट, अरावली बचाओ जैसे संगठनों ने लोगों को जागरूक किया है। युवाओं और पर्यावरणविदों द्वारा सोशल मीडिया और पदयात्राओं के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अरावली को “इको-सेंसिटिव जोन” के रूप में पूरी तरह सुरक्षित किया जाए।

अरावली को केवल कागजी कानूनों से नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए एक समता वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है: सेटेलाइट इमेजरी और ड्रोन के जरिए अरावली की सीमाओं का सटीक सीमांकन किया जाए ताकि एक इंच भूमि पर भी कब्ज़ा न हो सके।विदेशी पेड़ों को हटाकर स्वदेशी प्रजातियों के जंगल विकसित किए जाएं जो जल

—अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

रणकपुर जवाई बांध फेस्टिवल 2025 का समापन

पाली, (निसं)। मारवाड़-गोड़वाड़ की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर स्थापित करने की मंशा से जिला प्रशासन पाली, पर्यटन विभाग राजस्थान तथा नगरपालिका सादड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय रणकपुर जवाई बांध फेस्टिवल 2025 का रंगारंग समापन हुआ।

इस अवसर पर महोत्सव में पर्यटक वन्यजीवों को प्राकृतिक पर्यावास में देखकर रोमांचित हो उठे। इधर, रणकपुर स्थित हॉट एयर बैलुनिंग आयोजित हुआ। हेलीपैड ग्राउंड पर ही आयोजित रोचक प्रतियोगिताओं में भी सैलानियों ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल के दिन हॉर्स शो आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने सजे ध्वजे घोड़ों के करतबों पर दांतों तले उंगली दबा ली। हॉर्स पोलो के दौरान दर्शकों का उत्साह चरम पर रहा। वहीं दिनभर चली रोचक प्रतियोगिताओं और हॉर्स शो ने भी सैलानियों को रोमांचित किया। महोत्सव में रस्साकस्सी की महिला को प्रथम टीम में सुमन, सोनल, सीता, रेशमा, आशवंती, लक्ष्मी, आकांक्षा, दीपिका, कंचन, ललित, चम्पा प्रथम रही। इसी प्रकार पुरुष की रस्साकस्सी टी में रमेश चंद्र परिहार, रानुसिंह, रामेश्वर फिरोदा, बाबूलाल माली, ललित माली, मुकेश दवासी,



मिस गोडवाड़ प्रतियोगिता के विजेता को अधिकारियों ने पुरस्कृत किया।

पप्पू कुमार, जावेद टांक, भंवरलाल, नकुल कश्यप व जीतू चौधरी टीम प्रथम रही। गोडवाड़ श्री में प्रशांत वर्मा प्रथम एवं मिस गोडवाड़ में शारदा कुमार प्रथम रही। मूछ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर विक्रमसिंह, रॉसिंह चौहान प्रथम रहे, द्वितीय स्थान पर संदीप राठीड, तृतीय स्थान पर पोंकरलाल सोलंकी, धीरेन्द्र सिंह, देवा मारवाडी तृतीय रहे। साफा बांध प्रतियोगिता में संजय मंशान प्रथम, तेजवंत सिंह चौहान द्वितीय, तृतीय डिकेन्द्र सिंह सिन्घनिया,

तत्वावधान में फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी हुई। इसमें जिते भर के फोटोग्राफर्स ने प्राकृतिक, वाइल्डलाइफ, कल्चर व सांस्कृतिक विषय पर फोटोग्राफी कर प्रविष्टियां जमा कराईं। इन सभी फोटोग्राफ्स की यहां प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे दर्शकों ने देख के सराहा। फेस्टिवल के अंतिम दिन रात सूर्य मंदिर के समीप आयोजित कार्यक्रम में मामले खान के सुरों ने समा बांध दिया। मामले खान ने पधारों मारे देश गीत से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। साथ

बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूलों को व्याख्याता नहीं मिलेंगे

बीकानेर, (निसं)। 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेट सीट घोषित कर दी गई है। 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से और 9वीं व 11वीं कक्षा की 7 मार्च से शुरू होगी, लेकिन स्कूलों को व्याख्याता वार्षिक परीक्षा से पहले मिलने संभव नहीं होंगे। अभी तक व्याख्याताओं की वरिष्ठता तैयार नहीं हुई है। मंडल स्तर पर अस्थाई से स्थाई वरिष्ठता तैयार होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर से डीपीसी की तैयारी शुरू होगी, जिसमें अभी समय लगेगा। पिछले 3 साल से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की डीपीसी बकाया होने से रिक्र पदों का ग्राफ साल दर साल बढ़ता जा रहा है।

वर्तमान में राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्याख्याता 18649 पद रिक्त चल रहे हैं। व्याख्याता नहीं होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनेक स्कूलों में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों को 11वीं-12वीं कक्षा का बकाया कोर्स पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

■ **वर्तमान में राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्याख्याता के 18649 पद रिक्त चल रहे हैं**

■ **व्याख्याता नहीं होने से सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों को 11वीं-12वीं कक्षा का बकाया कोर्स पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई**

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी

बीकानेर, (निसं)। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं बोर्ड एग्जाम का कार्यक्रम जारी कर दिया है। शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा (कक्षा 5) का आयोजन आगामी वर्ष फरवरी से मार्च के बीच में किया जाएगा।

आठवीं के स्टूडेंट्स को होली के अवकाश में भी तैयारी करनी

होगी, जबकि पांचवीं के स्टूडेंट्स के एग्जाम पहले ही खत्म हो जाएंगे। सिर्फ संस्कृत स्कूल सहित विशेष स्कूलों में ही पांचवीं की तृतीय भाषा के एग्जाम होंगे।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी 2026 से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी, जबकि कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20

फरवरी 2026 से 5 मार्च तक आयोजित होंगी।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना विभागीय पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

कंटेनर में भरे गौवंश को मुक्त कराया

टोंक, (निसं)। निवाई क्षेत्र में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस और गौ सेवादल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर सोमवार रात्रि को दो दर्जन गौवंश से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है।

भ्राए जैनकर के अनुसार सोमवार रात्रि को गौवंश सेवादल को गांव चिकाना क्षेत्र से गौवंश से भरा

कंटेनर निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने कंटेनर का पीछा कर निवाई थाना क्षेत्र स्थित दशहरा मैदान के पास उसे घेरकर कर रोक लिया तथा थाना पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाकर कंटेनर व आरोपी चालक हनीफ खां (30) पुत्र चाव खां, निवासी जमातगढ़, थाना

पुनहाना, जिला नूंह (हरियाणा) को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद निवाई थाना पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर क्रेन की मदद से सभी गौवंश को सुरक्षित गौशाला भिजवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई प्रारम्भ की।

सरकार हर बेटी, हर महिला के साथ

सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की पक्की बात

हर बेटी, हर महिला के साथ... यह सरकार की वह प्रतिबद्धता है, जो संवेदनशीलता को नीति और संकल्प को परिणाम में बदलती है। महिलाओं और बालिकाओं के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक मजबूत ढांचे में पिरोया है। ये पहल केवल सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ने, निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का आधार प्रदान कर रही हैं। स्वच्छ रसोई की सुविधा से लेकर उच्च शिक्षा तक पहुंच, आर्थिक संबल से लेकर सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर निर्भीकता, सरकार का प्रयास है कि हर बेटी और हर महिला को बराबरी का अवसर और सम्मान मिले। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने नारीशक्ति को विकास की धुरी बनाते हुए एक समावेशी, सशक्त और संवेदनशील समाज की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।



आगे बढ़ रही बेटी

राजस्थान में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत 33,904 बेटी जन्मोत्सव समारोह आयोजित किए गए हैं। इसमें 1.95 लाख बालिकाओं के जन्मोत्सव मनाए गए तथा ग्राम पंचायतों पर 2.72 लाख वृक्षों का रोपण किया गया। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों की बेटीयों को वित्तीय सहयोग देना है जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई कर रही हैं। आपकी बेटी छात्रवृत्ति योजना राजस्थान में हर पात्र छात्रा को 2,100 से 2,500 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

सरकार की पहल से आसान हुई खेती



व्याज-मुक्त फसली ऋण सुविधा के माध्यम से सरकार किसानों को किरायेती और समय पर ऋण उपलब्ध कराने की बड़ी पहल कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 77.74 लाख से अधिक किसानों को 44,355 करोड़ रुपये से अधिक का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को व्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है, जिससे उनकी खेती की लागत घटाना आसान होता है और बीज, खाद व कीटनाशक जैसी आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध हो पाती है। नवीन कृषकों को 446.24 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किए गए हैं।

634.22 करोड़ रुपये के ऋण



डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए एक लाख रुपये तक व्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। इसमें 84,604 पात्र गोपालक परिवारों को 634.22 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। सभी दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है।

गांव-गांव पहुंचा उपचार

मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट पशुपालन विभाग की ऐसी पहल है, जिसके जरिए दूरदराज गांवों में पशुओं को चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें 536 मोबाइल वाहनों से करीब 58.64 लाख पशुओं का उपचार कर 14 लाख 48 हजार से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है।



- रसोई गैस सब्सिडी योजना में गरीब परिवार की महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध
- कृषि अध्ययन के लिए 58,397 छात्राओं को 103 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
- लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.50 लाख रुपये सेवा बॉण्ड से 4.60 लाख बालिकाओं को मिला लाभ
- 12 लाख महिलाएं बर्नी लखपति दीदी, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 216 करोड़ रुपये के ऋण
- प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 9.92 लाख गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपये की सहायता
- महिला अपराधों में 12 प्रतिशत की कमी, 65 एन्टी रोमियो स्कवॉड का गठन



हर नारी का मान

मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन सम्मान योजना द्वारा विधवा, परित्यक्ता, अकेली महिलाओं व जरूरतमंद महिलाओं को मासिक पेंशन, आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना में करीब 6,234 करोड़ रुपये व्यय कर 19.24 लाख पेंशनर्स को लाभ दिया गया है।

दीदी बनी लखपति

प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राजीविका मिशन के तहत 'लखपति दीदी' योजना का विस्तार किया गया है। इसके तहत करीब 19.45 महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण प्रदान कर 12.06 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है।

बिटिया की शिक्षा की राह हुई सुगम

सरकार ने कालीबाई भील निशुल्क स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूटी की राशि सीधे संबंधित एजेंसी के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। योजना में 39,664 स्कूटियों का वितरण किया गया है।

महिला सुरक्षा- एक और बढ़ा कदम



राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'कालिका पुलिसकर्मियों' की 500 'कालिका पेट्रोलिंग यूनिट' का गठन किया है। ये टीमें राज्य के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, जैसे कॉलेज, मॉल और धार्मिक जगहों पर गश्त करती हैं। यूनिट की वर्दी को खास डिजाइन किया गया है। इनके स्कूटर और हेलमेट काले रंग के हैं और वर्दी पर पीछे की ओर नियाँ मोनोग्राम होता है।

स्वच्छ ईंधन से सेहत

गरीब परिवार की महिलाओं को हानिकारक धुएं से बचाकर स्वस्थ प्रदान करने के लिए एक जनवरी, 2024 से रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चिह्नित लाभार्थियों तथा बीपीएल परिवारों (राजस्थान राज्य के) को रसोई गैस सिलेण्डर केवल 450 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लाभार्थियों को 4.82 करोड़ गैस सिलेण्डर सिफिलिंग कर 867 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

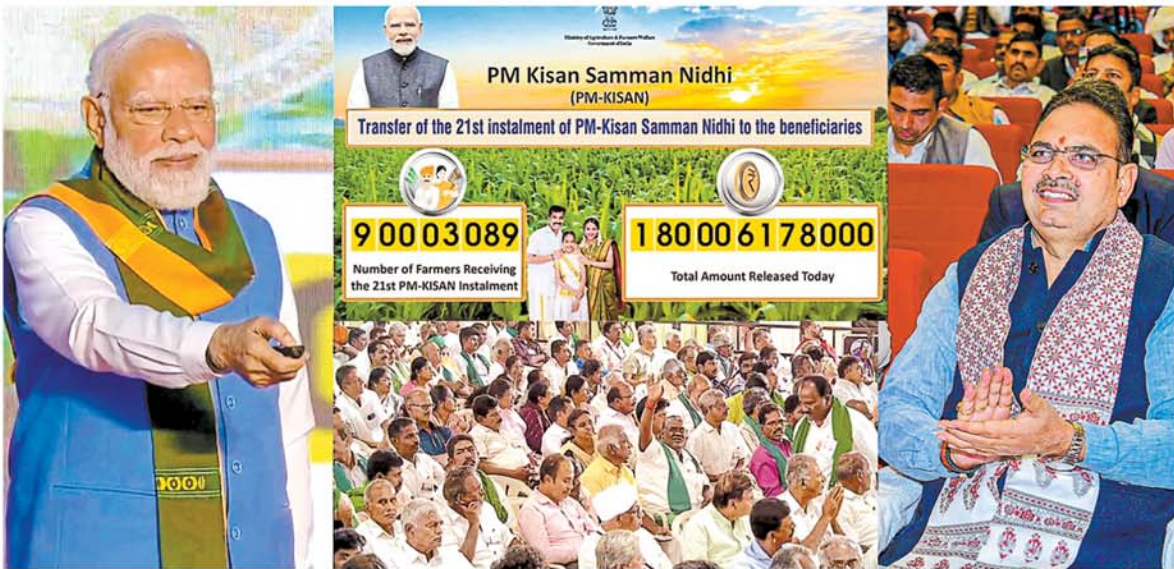
खिलखिला रही लाडो

लाडो प्रोत्साहन राशि पहले एक लाख थी जिसे भजनलाल सरकार ने बढ़ाकर अब 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। अब तक 4.60 लाख बालिकाएं प्रथम क्रिस्ट से लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना में परिवार को राजस्थान में बेटी के जन्म पर सेविंग बॉन्ड कुल सहायता राशि 1.5 लाख कुल 7 किस्तों में (जन्म, टीकाकरण, स्कूल-प्रवेश, कक्षा-उत्थान, स्नातक आदि के समय) दी जाती है। यह योजना स्वचलित है और इसके लिए अलग से फार्म भरने की जरूरत नहीं है।

किसान और पशुपालक के हित में ठोस प्रयास

खेत से घर तक विकास की नीति बनी ग्रामीण उत्थान का मजबूत आधार

ग्रामीण अंचलों की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए और किसानों-पशुपालकों के हर संघर्ष को अपना दायित्व मानते हुए राज्य सरकार ने विकास की ऐसी समग्र रूपरेखा तैयार की है, जिसमें सेवा, सुरक्षा और सशक्तीकरण तीनों का संतुलित समावेश दिखाई देता है। खेती और पशुपालन को केवल आजीविका नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानकर सरकार ने नीतियों को जमीन से जोड़ते हुए उन्हें परिणामोन्मुख बनाया है। दूरदराज गांवों और रेगिस्तानी क्षेत्रों तक पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच हो, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिले, फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिले, सिंचाई और बिजली की समस्याओं का समाधान हो या फिर डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित करनी हो, हर मोर्चे पर सरकार की मंशा स्पष्ट और प्रयास प्रभावी नजर आते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि किसानों और पशुपालकों में विश्वास, आत्मबल और भविष्य के प्रति आश्वस्ति भी पैदा की है। ये पहल इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार का विकास मॉडल कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव की चौपालों तक उपस्थिति दर्ज करा रहा है।



76.18 लाख किसानों को मिला 'सम्मान'

राज्य में वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ करने की घोषणा के बाद लाभार्थियों को हर साल 2,000 रुपये तीन किस्तों में देने की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस 2,000 की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 2025-26 में 3,000 रुपये कर दिया। योजना में किसानों को हर साल तीन किस्तों में 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब तक योजना में 71.79 लाख किसानों को 2,073 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के 76.18 लाख किसानों को अब तक 8 हजार 359 करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

खेती, पशुपालन और तकनीक का अपूर्व संगम

जनकल्याण से कृषक आत्मनिर्भरता तक समावेशी विकास



हर मुश्किल में सरकार साथ

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में किसानों को खेती करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अंग-भंग होने की स्थिति में आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाती है। योजना में 5,415 लाभार्थियों को 85.41 करोड़ रुपये की सहायता की गई है। इसके अलावा पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य में देश की सबसे अधिक क्षमता वाली विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।



बढ़कर मिल रहा बोनस

प्रदेश में वर्ष 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 125 रुपये एवं वर्ष 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं के समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर 150 रुपये का बोनस प्रदान कर 2575 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदकर किसानों को लाभान्वित किया गया। इस योजना में 2.66 लाख किसानों से 33.42 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और उन्हें 471.16 करोड़ रुपये बोनस दिया गया है।



तारबंदी योजना से मिली सुरक्षा

तारबंदी योजना के अंतर्गत आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसानों के खेतों में फेंसिंग (तारबंदी) पर अनुदान दिया जाता है। किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये निर्धारित है। लघु एवं सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत तक, अधिकतम 48 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। करीब 31,357 किलोमीटर की तारबंदी स्थापित कर 330 करोड़ रुपये से अधिक अनुदान दिया गया है।



किसान की नई डिजिटल पहचान

किसान डिजिटल आइडी के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जा रहा है। अब तक लगभग 75 लाख किसानों को यह डिजिटल पहचान उपलब्ध कराई जा चुकी है। इससे लाभार्थी सत्यापन सरल हो गया है, योजनाओं का लाभ एक क्लिक पर मिल जाता है। एग्रीस्टेक योजनान्तर्गत डिजिटल कृषि पहल के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री एवं डिजिटल क्राफ्ट सर्वे गिरदावरी योजनाएं शुरू की गई हैं।

6206.61 करोड़ के क्लेम वितरित



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लागू की गई है। योजना में किसानों की फसल को बुआई से लेकर कटाई होने के बाद तक आने वाली मौसम की मार या प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा दी जाती है। इससे किसान बिना डर के खेती कर सकते हैं और नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा भी मिलता है। बीते दो साल में योजना के तहत अब तक 6206.61 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं एवं देश में सर्वाधिक 2.19 करोड़ बीमा पॉलिसियों का सृजन किया गया है।

महिला की हत्या के बाद शव बोरे में बंद कर फेंकने वाला पड़ौसी गिरफ्तार

पैसों के विवाद में महिला के गले और सिर पर वार कर हत्या की थी

जयपुर (कासं)। शास्त्री नगर इलाके में बोरे में बंद महिला का शव मिलने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या कर शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने वाले आरोपी पड़ौसी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पैसों के विवाद में महिला की नृशंस हत्या करना स्वीकार किया है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जयपुर उत्तर) बजरंग सिंह ने बताया मंगलवार सुबह सुभाष कॉलोनी, शास्त्रीनगर स्थित एक मकान के पोर्च में प्लास्टिक के बोरे से दूर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे से महिला का शव बरामद किया। मृतका की पहचान बबीता शर्मा (50) निवासी शास्त्री नगर के रूप में हुई। शव को कंबल में लपेटकर बोरे में पैक किया गया था और चेहरे व सिर पर गंभीर चोट के निशान

■ हत्या के बाद करीब 30 घंटे तक शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में था आरोपी

मिले थे। इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मिश्रल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने त्वरित जांच करते हुए आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू उर्फ राहुल (36) निवासी सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका बबीता शर्मा उसकी परिचित थी और दोनों के बीच लंबे समय से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी ने 21 दिसंबर को धारदार हथियार से महिला के गले और सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद करीब 30 घंटे तक शव को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा। सबूत मित्दाने के लिए घर के फर्श को कई बार धोया और खून

से सने कपड़े नाले में फेंक दिए। बाद में रात के समय शव को बोरे और कंबल में लपेटकर पास के मकान के खुले गेट से घसीटते हुए पोर्च में डाल दिया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जयपुर उत्तर) बजरंग सिंह ने बताया कि आरोपी ने मकान हाल ही में बेच दिया था। जिससे किसी को उस पर शक न हो। ऐसी योजना उसने बनाई थी। घटना के बाद वह आसपास भीड़ में शामिल होकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त करण शर्मा ने बताया कि, मंगलवार सुबह सुभाष कॉलोनी स्थित परशुराम पार्क के पास 3 मंजिला मकान के पोर्च में प्लास्टिक के बोरे में शव मिला। यह मकान ठेकेदार सूरज प्रकाश सांवरिया का है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर उनकी पत्नी मुन्नी देवी रहती है

और ऊपर के दो फ्लोर पर किराएदार रहते हैं।मंगलवार सुबह पोर्च में पड़े बोरे को पहले किराएदारों का सामान समझा गया, लेकिन जांच करने पर उसमें महिला का शव मिला। मृतका की पहचान बबीता शर्मा (50) निवासी शास्त्री नगर के रूप में हुई है।

डॉग स्कॉड की मदद से पुलिस ने पकड़ा आरोपी

डॉग स्कॉड की जांच के दौरान पुलिस का श्वान वारदात स्थल से कुछ दूरी पर स्थित पड़ौसी के घर पहुंचा। इस आधार पर पुलिस ने पड़ौसी युवक जीतू को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि जीतू ने कुछ समय पहले अपना मकान 5.5 लाख रुपये में बेच दिया था और वह कभी-कभी इसी इलाके में रुकने आता था।

सरस राजसखी मेले में हस्तशिल्प के साथ लोकरंग की धूम मची

जयपुर (कासं)। “भारत – एक सूत्रधार” की थीम पर आधारित सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला-2025 इन दिनों लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प, वस्त्र, व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भारतीय विविधता की एक जीवंत तस्वीर पेश कर रही है।

मेले के दौरान एनआईएफ रोलबल जयपुर, कमला घोषार इंस्टीट्यूट एवं राजीविका के संयुक्त तत्वावधान में डिजिटल सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु एक जागरूकता नाट्य प्रस्तुति भी दी गई। इस प्रस्तुति से यह संदेश दिया गया कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन और प्रभावी प्रोजेक्टेयन से ग्राहक जुड़ाव बेहतर होता है, वहीं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और कैशलेस लेन-देन आज के डिजिटल युग में व्यवसाय की आवश्यकता बन चुके हैं। मेले में मंगलवार को टेक्स्टाइटल सेक्शन में खास तौर पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित



सरस राजसखी मेले में मंगलवार को लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं।

कई राज्यों से आए पारंपरिक वस्त्र अपनी विशिष्ट पहचान और आकर्षक बनावट के कारण खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। रंग-बिरंगे परिधान, बारीक हस्तनिर्मित डिजाइन, पारंपरिक कढ़ाई और क्षेत्रीय कला की झलक ने खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी लोक

नृत्य और मधुर मांड गायन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य-जबिजा और जाट-जलिन-की जीवंत और भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। दर्शकगण तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन करते नजर आए और पूरा परिसर उत्सवधर्मी वातावरण में ढिखा।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों के नाम पर बनाए राजस्व गांव रद्द किए

जयपुर (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने बाड़मेर जिले के दो राजस्व गांवों के नाम भूमि दान करने वालों के नाम पर रखने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना राज्य सरकार के 20 अगस्त, 2009 के परिपत्र के खिलाफ है। यह परिपत्र किसी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर राजस्व गांव के नामकरण पर रोक लगाती है। जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे को खंडपीठ ने यह आदेश भीष्मा राम की याचिका पर दिए।

मामले के अनुसार राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर कई राजस्व गांव बनाए थे। इसमें बाड़मेर जिले के सोहदा गांव की मेघवालों की ढाणी से अलग किए अमरगढ़ और सतसत गांव भी शामिल थे। अधिसूचना से पहले तहसीलदार ने प्रमाणित किया था कि सभी

औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और प्रस्तावित गांव किसी व्यक्ति, धर्म या जाति आदि से जुड़े नहीं हैं। वहीं बाद में सीमांकन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने यह आपत्ति दर्ज कराई कि अमरगढ़ और सतसत नाम भूमि दान करने वाले अमरराम और सगत सिंह के नाम पर लिए गए हैं। इसके बाद 2020 की अधिसूचना को हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने माना की दोनों गांवों के नामांकरण में साल 2009 के परिपत्र की अवहेलना की गई है। इसके साथ ही एकलपीठ ने अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ पेश अपील पर खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्टने हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया।

उड़ीसा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की खनन कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करेंगे प्रदेश के अफसर

नियम-प्रक्रियाओं, अनुमतियों, अवैध खनन पर कार्रवाई और राजस्व वृद्धि का होगा अध्ययन

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार ने उड़ीसा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की खनन क्षेत्र की कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेज) का अध्ययन दान करने वाले अमरराम और सगत सिंह के नाम पर लिए गए हैं। इसके बाद 2020 की अधिसूचना को हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने माना की दोनों गांवों के नामांकरण में साल 2009 के परिपत्र की अवहेलना की गई है। इसके साथ ही एकलपीठ ने अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ पेश अपील पर खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की गई। जिस पर सुप्रीम कोर्टने हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया।



प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने खनन अधिकारियों की बैठक ली।

तकनीक के उपयोग के साथ ही राजस्व प्राप्त की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगी। उन्होंने बताया कि अध्ययन दल को इन राज्यों की खनन क्षेत्र की बेस्ट प्रैक्टिसेज का भी अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह दल प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा तीनों राज्यों को भेजे जाने वाले दल में अधीक्षण खनि अभियंता स्तर के अधिकारी के साथ ही



प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने खनन अधिकारियों की बैठक ली।

तकनीक के उपयोग के साथ ही राजस्व प्राप्त की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगी। उन्होंने बताया कि अध्ययन दल को इन राज्यों की खनन क्षेत्र की बेस्ट प्रैक्टिसेज का भी अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह दल प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा तीनों राज्यों को भेजे जाने वाले दल में अधीक्षण खनि अभियंता स्तर के अधिकारी के साथ ही

हरियाणा से मॉर्डन ड्रग लाकर जयपुर में बेचने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी में युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले तस्करी के खिलाफ जयपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने मंगलवार को दांसपोट नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एमडी (सिंथेटिक ड्रग) की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 53

■ पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 53.72 ग्राम एमडी और एक कार जब्त की

ग्राम 7.2 मिलीग्राम एमडी तथा तस्करी में प्रयुक्त एक कार जब्त की गई है। जब एमडी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5.50 लाख रुपये बताई जा रही है। विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तरुण सिंह निवासी सोडाला, लोकेंद्र सिंह निवासी मजदूर नगर और प्रशांत शर्मा निवासी वैशाली नगर के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि तीनों आरोपी हरियाणा से एक नाइजीरियन



जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने मंगलवार को दांसपोट नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक ड्रग तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

तस्करी हेनरी से एमडी खरीदकर जयपुर में युवाओं के बीच सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी युवाओं को नशे का आदी बनाकर बड़े नेटवर्क के जरिए ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। पूछताछ में नशे के कारोबार से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं, जिनकी तस्करी की जा रही है।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि जयपुर में इनके साथ और कौन-कौन लोग इस अवैध धंधे में शामिल थे। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि यह एक संगठित और लंबा नेटवर्क है।

आरोपियों द्वारा बताए गए ठिकानों पर सीएसटी की टीम लगातार दबिश दे रही है। पूछताछ में उन लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जो इनसे एमडी लेकर आगे सप्लाई करने वाले थे। पुलिस का दावा है कि इस मामले में आने वाले दिनों में करीब आधा दर्जन और गिरफ्तारियां संभव हैं।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जयपुर में नशे की तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

■ सार-समाचार

‘नखराली नार’ कार्यक्रम में बिखरे लोकरंग



जयपुर। गणगौर महिला ग्रुप की ओर से आयोजित “नखराली नार” कार्यक्रम में राजस्थान की रंग-बिरंगी लोक संस्कृति साकार हो उठी। ग्रुप फाउंडर और डायरेक्टर सुशीला भारती ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी महिलाएं राजस्थानी रंग बिरंगे परिधान और ज्वेलरी में सभ्य-धन कर आईं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण चरी नृत्य रहा जिसमें किरण मौर्य ने पहला और इति कुमार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। विशिष्ट अतिथि मीना श्रीवास्तव ने ट्रॉफी और पुरस्कार देकर विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर रैंप वॉक भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रुप के छः वर्ष पूरे होने पर सभी महिलाओं ने केक काटकर उत्सव मनाया। कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाओं ने राजस्थानी लोक गीतों पर ग्रुप डांस करके धमाल किया।

विद्यार्थियों को स्टेटर-जुराब व जूते बांटे



जयपुर। राजस्थान पेंशनर समाज, उप शाखा मालवीय नगर जयपुर ने अपने सामाजिक सरोकारों के तहत मंगलवार को द्वितीय चरण में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दहलावास, प्रताप नगर सांगानेर में 160 स्टेटर एवं 160 जुराब का वितरण प्रधानाचार्य रामफूल राधोया के निर्देशन में किया। इस अवसर पर संरक्षक सतीश गुप्ता द्वारा 100 बच्चों को जूते और स्कूल के लिए 10 दरिया भी भेंट की गई। इससे पूर्व स्कूल स्टाफ तथा छात्रों द्वारा पेंशनर समाज के सदस्यों का तिलक लगा कर एवं माला पहना कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पेंशनर समाज के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद थे। संस्था के उप सचिव बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि पेंशनर समाज उप शाखा मालवीय नगर द्वारा पिछले 15 वर्ष से जरूरतमन्द स्कूली बच्चों को स्टेटर, जुराब आदि वितरित किये जा रहे हैं। पहले चरण में सोमवार को 192 स्टेटर और जुराब आदि वितरित किये गए थे।

“सफ़र-ए-शहादत वॉक” 25 को

जयपुर (कासं)। जयपुर की सुखमनी सेवा सोसायटी बनी पार्क द्वारा साहिबजादों की लसानी शहादत को समर्पित सफ़र-ए-शहादत वॉक 25 दिसंबर को आयोजित की जायेगी। यह आयोजन गुरुद्वारा चौड़ा रास्ता प्रबंधक और गुरुद्वारा चांदी की टकसाल प्रबंधक कमेट्री के सहयोग से किया जा रहा है। वॉक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव सत्संग सभा, चौड़ा रास्ता से सुबह 9 बजे आरंभ होकर 11 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा, चांदी की टकसाल में सम्पन्न होगी। जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। सोसायटी के सचिव, सूर्य उदय सिंह ने बताया कि इस वॉक में लगभग 40-50 बच्चे सिख वेशभूषा में सम्मिलित होंगे। तख्तियां और बैनर के साथ साहिबजादों की शहादत और सिख मर्यादा का जीवंत संदेश देंगे। वॉक के दौरान शहीदी का संदेश देते हुए मोबाइल होर्डिंग भी साथ चलाएंगे। इसके साथ ही, अमृतसर की अमृतोज गतका अकैडमी के बच्चों द्वारा गतके के रोमांचक कतब प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रस्तुति के माध्यम से सिख वीरता और शौर्य की गौरवशाली परंपरा पर प्रकाश डाला जाएगा।

किसान अधिकार-सशक्तिकरण पर मंथन

जयपुर। भारत रत्न से सम्मानित, किसान मसीहा एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से यह कार्यक्रम जयपुर के पिकसिटी प्रेस क्लब में किया गया। समारोह अध्यक्षता राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना ने की। समारोह में किसानों के अधिकार, सम्मान एवं सशक्तिकरण को लेकर सार्थक, सकारात्मक एवं विचारोत्तेजक संवाद हुआ। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) त्रिलोक त्यागी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी एवं भामाशाह विजय पुनिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि त्रिलोक त्यागी ने भारत रत्न स्व. चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना सहित प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। त्यागी ने कहा कि, आरएलडी प्रदेश के सभी जिलों में स्व. चौधरी चरण सिंह के विचारों पर संगीष्ट कराएंगे।

मुख्यमंत्री व शिवराज सिंह ने मेड़ता में किसानों को 1200 करोड़ रु. हस्तांतरित किये

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2000 करोड़ रु. के स्वीकृति पत्र सौंपे

नागौर/जयपुर, 23 दिसम्बर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि किसानों का फसल उत्पादन बढ़े तथा उनकी लागत में कमी आए।

चौहान मंगलवार को राज्य

■ किसान सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट तथा पैस्टिसाइड एक्ट लाने वाली है, जिससे नकली पैस्टिसाइड व महंगे बीज देने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी।

सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेड़ता में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत दो वर्षों में राजस्थान में विकास का नया अध्याय रचा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के किसानों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर 9 हजार रुपये किया है।

चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट एवं पैस्टिसाइड एक्ट लाने वाली है जिससे नकली पैस्टिसाइड एवं महंगे बीज देने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है तथा शीघ्र ही वंचित गरीबों को मकान देने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि किसान हमारे राष्ट्र के असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है तब अन्नदाता अपने खेतों में जागते हैं।



केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को मेड़ता में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरु ने मुख्यमंत्री को हल भेंट किया।

चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो या आंधी तूफान, किसानों का काम कभी नहीं रुकता। उन्होंने कहा कि वे स्वयं एक किसान रहे हैं इसलिए वे खेती में आ रही समस्याओं को भली-भांति समझते हैं।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी, 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली जैसे अनेक किसान हित में निर्णय लिए

हैं। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले बैच में 3 हजार 200 किलोमीटर से अधिक की 1,216 सड़कों एवं एक पुल के लिए 2 हजार 89 करोड़ रुपये के कार्यों का स्वीकृति पत्र सौंपा। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री ने कृषक कल्याण योजनाओं के तहत 35 हजार 800 किसानों को 187.60 करोड़ रुपये की राशि उनके

खातों में हस्तांतरित की। साथ ही, 5 लाख कृषकों को कृषि आदान अनुदान के रूप में 617 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि भी खातों में भेजी गई।

उन्होंने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को 150 करोड़ रुपये की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 18 हजार 500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी की।

बांग्लादेश उच्चायोग पर भारतीयों का गुस्सा फूटा

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक बयान में कहा, “बांग्लादेश इस तरह की पूर्व-नियोजित हिंसा या राजनयिक प्रतिष्ठानों को डराने-धमकाने की घटनाओं की निंदा करता है, जो न केवल राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि आपसी सम्मान और शांति व सहिष्णुता के

मूल्यों को भी कमजोर करती है।”

मंत्रालय ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि इससे राजनयिक कर्मियों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा है और भारत से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

बयान में कहा गया, “बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया

है कि वह इन घटनाओं की गहन जांच कराए, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए और भारत में बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों तथा उनसे जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।”

इन घटनाओं में 22 दिसंबर 2025 को सिलीगुड़ी स्थित बांग्लादेश

देश भर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उत्तरकर विरोध प्रदर्शन किया है, उनका कहना है कि सरकार अरावली को खनन माफिया और भूमाफियाओं को बेचने की कोशिश कर रही है, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचाने का बड़ा जोखिम पैदा करेगा।

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस डर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि जब तक एक वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार और अनुमोदित नहीं की जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली में से केवल 0.19 प्रतिशत ही खनन के योग्य है। अवैध खनन के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए मंत्री ने कहा कि नया नियम ऐसे कार्यों पर नियंत्रण लगाएगा और “कानूनी रूप से सतत खनन” की अनुमति देने के उद्देश्य से है। हालांकि, उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अवैध खनन गतिविधियों पर कैसे रोक लगाई जाएगी। एक्टिविस्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अरावली की नई परिभाषा के कारण स्थिति ऐसी बन जाएगी कि 90 प्रतिशत पहाड़ियां अब अरावली के रूप में नहीं मानी जाएंगी। मंत्री ने यह स्पष्ट करने में विफलता जताई कि कितनी पहाड़ियां संरक्षित की जाएंगी और कितनी प्रभावित होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2010 में फॉरेस्ट सर्वे इंडिया भारत की एक रिपोर्ट में यह सामने आया था कि अरावली की लगभग 12,000 पहाड़ियों में से केवल 8 प्रतिशत पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं।

दुष्कर्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील रचना मान ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर कई बार संबंध बनाए हैं।

पूरे पुराने बंगाल प्रांत में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोषियों को सजा नहीं मिली है। इतना ही नहीं, पुलिस थाने आम तौर पर मुस्लिम अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से भी इनकार कर देते हैं।

इसके बावजूद, ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब उनके लिए पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही है। एक मुस्लिम, जो मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ को कम कर रहा है वह उन्हीं के जैसा एक व्यक्ति है और उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा है। हुमायूँ कबीर नामक एक दलबदलू नेता, जो पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता रहा है, ने अब अपनी नई पार्टी बना ली है और अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दे रहा है। कबीर ने पहले मुर्शिदाबाद जिले में हिंदुओं को “काटने” और लाशों को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की धमकी दी थी। उसने यह दावा किया था कि मुर्शिदाबाद की आबादी में 80 प्रतिशत मुस्लिम है।

पश्चिम बंगाल से भी कहीं ज्यादा भयावह हालात बंगाल के दूसरे हिस्से, यानी बांग्लादेश में हैं, जहां इतनी हिंसा फैल चुकी है जो हाल के वर्षों में शायद ही कभी देखी गई है। कट्टर इस्लामी भीड़ देश में तबाही मचा रही है और हिंदुओं पर हमले बेहिसाब बढ़ गए हैं।

बांग्लादेश में एक हिंदू गारमेट मजदूर की नृशंस हत्या ने भारत में गंभीर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। हैरानी

- बांग्लादेश में इस्लामिक जूनून, जो पाकिस्तानी व बांग्लादेश के जमाती धर्मालम्बियों के आपसी सहयोग से चरम पर पहुंच गया है, का निशाना भी उस देश में रहने वाला आम हिन्दू ही है।
- यह माना जा रहा है कि यह हिंसा का दौर, प.बंगाल के चुनाव तक यँ ही बढ़ता जायेगा, पर फिर क्या इस नाग को दोबारा पिटारी में बंद किया जा सकेगा।

की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इस घटना का लगभग कोई असर नहीं दिखा और शायद ही कोई इसकी परवाह कर रहा है। यह ममता बनर्जी और उनकी तुणमुल कांग्रेस के आदेशों के आगे पूरी तरह झुके होने की स्थिति को दर्शाता है। एक व्यक्ति की अमानवीय हत्या को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में खुशी-खुशी प्रसारित किया गया, जिसमें दर्जनों हमलावरों को मृत शरीर को रौंदते हुए और बाद में उसके क्षतविक्षत शरीर को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया। यह सब बांग्लादेशी समाज में बढ़ती बर्बरता को उजागर करता है।

दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन हुए हैं और प्रमुख विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर सरकार की चुप्पी की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार के मौन रहने पर हमला बोला है, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इतनी बर्बरता के सामने केंद्र के चुप रहने की निंदा की है।

पिछले सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश अराजकता की स्थिति में है, जब बड़े जनविद्रोह के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थीं। तब से एक अंतरिम सरकार सत्ता में है, जिसके दौरान अपराध और हिंसा का बोलबाला रहा है।

यह सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के जमातियों की मदद से कराया था और इसके बाद से इस्लामी हिंसा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है। वर्तमान हिंसा की शुरुआत तब हुई जब एक राजनीतिक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद कई अन्य लोगों पर भी हमले हुए और अब पूरे देश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। अंतरिम सरकार सत्ता में आने के बाद से देश में थोड़ी भी व्यवस्था लाने में पूरी तरह नाकाम रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑपरेंटर कई कट्टरपंथी ताकतों को नियंत्रित कर रहे हैं।

अंकिता भंडारी मर्डर, एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा रहे हैं कि गौतम ने ऋषिकेश के पास एक रिसॉर्ट में काम करने वाली अंकिता का यौन शोषण करने की कोशिश की थी। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि उनके पास हत्या से जुड़े अतिरिक्त साक्ष्य हैं, जो उनके आरोपों की पुष्टि करते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या सितंबर 2022 में एक रिजॉर्ट में हुई थी, जो कथित तौर पर विनोद आर्य, जो उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, के बेटे पुलकित आर्य और कार्यकर्ताओं के पास था। उस समय विनोद आर्य माटी आयोग के अध्यक्ष थे, तथा उनका स्तर मंत्री का था। कुछ महीने पहले हत्या के दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला जब पहली बार सामने आया था, तब उत्तराखंड में व्यापक जन आक्रोश फैला था और विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन नए वीडियो के सामने आने से सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर

राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। दिल्ली में, उत्तराखंड कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा नियंत्रित केंद्र और राज्य सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

पार्टी ने धमकी दी है ऐसा नहीं हुआ तो गढ़वाल मंडल के प्रमुख कार्यालय में धरना और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलवार को नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने इस “भयंकर और नृशंस हत्या” की सीबीआई जांच की मांगों को नज़रअंदाज किया है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की, गोदियाल ने कहा, कि

भाजपा के प्रभावशाली लोग इस मामले में संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

गोदियाल के अनुसार, केंद्रीय जांच “जानबूझकर रोक की गई” क्योंकि यह रिसॉर्ट कथित तौर पर शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो “अवैध और अमानवीय गतिविधियों” में शामिल थे। उन्होंने इस मामले में शामिल सभी भाजपा नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस बीच, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई गैर-भाजपा राजनीतिक दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग की है, और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है जो इस युवा लड़की के यौन शोषण और हत्या में कथित रूप से शामिल हैं। वायरल वीडियो ने यह सुनिश्चित किया है कि अंकिता भंडारी मामला फिर से राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया है, और सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस पर निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दे।

TRUE VALUE

इस क्रिसमस कार लेना हुआ आसान । सिर्फ ₹59 प्रतिदिन# की आसान किश्तों में ।

CELEBRATING 60Lakh STORIES OF TRUST

यहाँ ऐप डाउनलोड करें।

यहाँ ऐप डाउनलोड करें।

ट्रस्ट

✓ वेरिफाइड कार हिस्ट्री**

✓ 3 फ्री सर्विसेज** 5000 से अधिक मारुति सुजुकी सर्विस स्टेशनों पर उपलब्ध

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruvalue.com

*नियम एवं शर्तें लागू। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया निकटतम डीलरशिप पर संपर्क करें। **वेरिफाइड कार हिस्ट्री और वारंटी केवल ट्रू वैल्यू प्रमाणित कारों पर लागू। निःशुल्क सेवा केवल श्रम शुल्क पर लागू है। दर्शाई गई छवियाँ केवल प्रतिनिधिक उद्देश्य के लिए हैं। *ऋण राशि ₹1 00 000 मानी गई है। ऋण की अवधि 84 महीने @ 80।11% वार्षिक ब्याज दर पर ली गई है। डाउन पेमेंट कार के मूल्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। फाइनेंस पूरी तरह बैंक या वित्तीय संस्था की मंजूरी पर निर्भर है और ग्राहक प्रोफाइल के अनुसार बदल सकता है।

क्वालिटी

✓ 376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

✓ 1 साल तक की वारंटी**

आसान फाइनेंस विकल्प* उपलब्ध हैं ।

TRUE VALUE CERTIFIED

UDAIPUR: S-140, MADRI INDUSTRIAL AREA, UDAIPUR, NAVNEET MOTORS: 7230016838, 9929140770, 8209069304 | SUKHER, 200 FEET ROAD, SUKHER BYE PASS, KHELGAON ROAD, NEAR BHERAVGARH RESORT, UDAIPUR, TECHNOY MOTORS: 8112266227, 9773346347, 9001237506, 9773346344 | BANSWARA: THIKARIA DAHOD ROAD, BANSWARA, NAVNEET MOTORS: 7665887333, 7597349534.

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वैस्ट्री मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●